



केलकता पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज यह मांग करते हुए क प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से आधारकर्ड के जो ने क अपना पैसला तत्काल वापस लेना चाहिए।

प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के केवल 15 फीसदी लोगों के ही आधार कर्ड मलि पाया है, ऐसे में 85 फीसदी लोग (साल में) नौ सब्सिडीप्राप्त सलेंडर नहीं ले पांगे, क्योंकि केंद्र ने सीधे ही संबंधित बैंक में सब्सिडी पहुंचाने के ली आधार कर्ड प्रत्यक्ष नकद अंतरण से जो दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार इस पैसले से आम जनता भारी परेशानी में आ जागी।

संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन में यह प्रस्ताव रखा था। विपक्ष के नेता सूर्य कंत मशिरा ने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि आधार कर्ड से जुई कई मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।

मशिरा ने कहा कि केंद्र कनूनी रूप से बायोमैट्रिकपंजीकरण के अनविर्य नहीं कर सकता।

चटर्जी ने प्रस्ताव में चटर्जी के इस लाईन को शामिल कर लिया कि आधार कर्ड के संबंध में कई मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।

माकमा सदस्यों ने इसका स्वागत किया।

(भाषा)